



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 68]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 13, 2012/फाल्गुन 23, 1933

No. 68]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 13, 2012/PHALGUNA 23, 1933

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 मार्च, 2012

विषय : चीन जन.गण. तथा जापान मूल के अथवा वहां से निर्यातित पेरॉक्सोसल्फेट (जिसे पेरसल्फेट के नाम से भी जाना जाता है) के आयातों के संबंध में लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की सनसेट समीक्षा।

सं. 15/9/2011-डीजीएडी.— यतः समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे एतदपश्चात अधिनियम कहा जाएगा) तथा समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियम, 1995 (जिन्हें एतदपश्चात पाटनरोधी नियम कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए अंतिम (निर्णायक) पाटन-रोधी शुल्क की सिफारिश मूलतः चीन जन गण तथा जापान (जिन्हें एतदपश्चात संबद्ध देश कहा गया है) के मूल अथवा वहां से निर्यातित पेरॉक्सो सल्फेट जिसे पेर सल्फेट के नाम से भी जाना जाता है (जिसे एतदपश्चात संबद्ध वस्तु कहा गया है) के आयातों में दिनांक 20 जुलाई, 2007 के अधिसूचना सं० 14/1/2006-डी.जी.ए.डी. पर की गई थी तथा चूंकि दिनांक 29 अगस्त, 2007 को केन्द्र सरकार ने अधिसूचना सं० 96/2007- सीमाशुल्क जारी कर उपर्युक्त पाटनरोधी शुल्क लगाया है।

2. यतः मै० गुजरात परसाल्ट्स प्रा० लिमिटेड, मै० कैलिबर केमिकल्स प्रा० लिमिटेड, मै० वी.आर. पेरसल्फेट तथा मै० योयो केमिकल्स ने संयुक्त रूप से निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें एतदपश्चात प्राधिकारी कहा गया है) के पास नियमावली तथा पाटनरोधी नियमावली के अनुसार संयुक्त रूप से एक विधिवत प्रमाणित आवेदन दायर किया है जिसमें संबद्ध देशों के मूल से अथवा वहाँ से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के पाटन का आरोप लगाया गया है और पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा करने, उसे जारी रखने और उसका संवर्धन करने का अनुरोध किया है।

घरेलू उद्योग

3. यह आवेदन मै0 गुजरात परसाल्ट्स प्रा0 लिमिटेड, मै0 कैलिबर केमिकल्स प्रा0 लिमिटेड, मै0 वी.आर. पेरसल्फेट्स तथा मै0 योयो कैमिकल्स द्वारा संयुक्त रूप से दायर किया गया है। आवेदकों द्वारा दावा किया है कि वे घरेलू उद्योग का प्रतिनिधित्व करते हैं क्योंकि सिर्फ वे ही संबद्ध वस्तुओं के घरेलू उत्पादक हैं। रिकार्ड में उपलब्ध सूचना के अनुसार आवेदक संबद्ध वस्तुओं के कुल भारतीय उत्पादक हैं तथा पाटनरोधी नियमों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार वे घरेलू उद्योग बनते हैं।

विचाराधीन उत्पाद तथा समान वस्तु

4. मूल जाँच में शामिल उत्पाद पेरॉक्सोसल्फेट (जिसे पेरसल्फेट के नाम से भी जाना जाता है) है। यह सनसेट समीक्षा जाँच है, अतएव, जाँच उसी उत्पाद को कवर करती है जैसाकि मूल जाँच में कवर किया गया है। पेरसल्फेट निकटतः संबंधित यौगिकों का एक समूह है। ये अल्कली मेटल साल्ट्स के रूप में उत्पादित होते हैं जिसमें अमोनियम पेरसल्फेट (ए पी एस) पोटेशियम पेरसल्फेट (पी पी एस) तथा सोडियम पेरसल्फेट (एस पी एस) शामिल हैं।

5. इन "पेरसल्फेट्स" का रसायनिक सूत्र क्रमशः $(\text{NH}_4)_2\text{S}_2\text{O}_8$, $\text{K}_2\text{S}_2\text{O}_8$, $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_8$ है। पेरसल्फेट के तीन प्रकार वस्त्र तथा रसायनिक उद्योगों में प्रवर्तक तथा आक्सीकरण एजेंट के रूप में इस्तेमाल होता है तथा एक को दूसरे से प्रतिस्थापित किया जा सकता है। सभी तीनों लवण एक और समान उत्पाद है। "पेरसल्फेट" वस्त्र एवं रसायनिक उद्योगों में प्रवर्तक तथा आक्सीकरण एजेंट के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं।

6. सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के उपशीर्ष 283340 के तहत तथा उपशीर्ष 28334000 के तहत अध्याय 28 में वर्गीकृत हैं।

7. घरेलू उद्योग समान लक्षणों तथा विशेषताओं वाले "पेरसल्फेट" का उत्पादन करता है। विचाराधीन उत्पाद अथवा समान वस्तु के मुद्दे पर पूर्व जाँच में किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा कोई तर्क नहीं किया गया है। वर्तमान जाँच पूर्व आरोपित पाटनरोधी शुल्क की सनसेट समीक्षा है। अतः प्राधिकारी मानता है कि घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित उत्पाद पाटनरोधी नियमावली के अनुसार विचाराधीन उत्पाद के "समान वस्तु" है।

जाँच शुरूआत

8. घरेलू उद्योग की ओर से तथा पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 द्वारा पठित अधिनियम के खण्ड 9ए (5) के तहत दायर विधिवत प्रमाणित आवेदन को ध्यान में रखते हुए, संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के संदर्भ में पाटनरोधी शुल्कों को लगातार लगाए जाने हेतु आवश्यकता की समीक्षा के लिए प्राधिकारी सनसेट समीक्षा जाँच की शुरूआत करते हैं तथा यह जाँच करना कि क्या इस प्रकार के शुल्क की समाप्ति से घरेलू उद्योग को पाटन तथा क्षति के जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

शामिल देश

9. इस जाँच में शामिल देश चीन जन.गण. तथा जापान हैं ।

जाँच की अवधि:

10. वर्तमान समीक्षा के प्रयोजनार्थ जाँच की अवधि 1 जनवरी, 2011 से 31 दिसम्बर, 2011 (12 महीने) है । तथापि क्षति विश्लेषण में वर्ष 2008-09, 2009-10, 2010-11 तथा जाँच की अवधि शामिल होंगी । पाटन तथा क्षति की संभावना को निर्धारित करने में जाँच की अवधि के बाहर के आँकड़ों की भी जाँच की जाएगी ।

11. समीक्षा में दिनांक 20 जुलाई, 2007 की अधिसूचना सं. 14/1/2006-डीजीएडी के सभी पहलुओं को शामिल किया गया है (मूल जाँच के अंतिम परिणाम) ।

12. उपर्युक्त नियमों के नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 और 20 के प्रावधान इस समीक्षा में यथाआवश्यक परिवर्तन के साथ लागू होंगे ।

सूचना प्रस्तुत करना

13. संबद्ध देश के ज्ञात निर्यातकों, भारत में स्थित उनके दूतावासों के माध्यम से संबद्ध देश की सरकार, भारत में उत्पाद से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों एवं प्रयोक्ताओं को निर्धारित प्रपत्र में और ढंग से संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए और प्राधिकारी को निम्नलिखित पते पर अपने विचारों से अवगत कराने के लिए अलग से लिखा जा रहा है :-

निर्दिष्ट प्राधिकारी
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय
वाणिज्य विभाग
कमरा सं. 240, उद्योग भवन
नई दिल्ली - 110107

कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे निर्धारित समय-सीमा के भीतर निर्धारित प्रपत्र में एवं ढंग से जाँच से संगत सूचना प्रस्तुत कर सकता है ।

समय-सीमा

14. वर्तमान जाँच से संबंधित कोई सूचना तथा सुनवाई हेतु कोई अनुरोध लिखित में भेजा जाए जो प्राधिकारी के पास उपर्युक्त पते पर इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस (40) दिनों के भीतर पहुँच जाना चाहिए । यदि निर्धारित समय-सीमा में कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अपूर्ण है तो प्राधिकारी पाटनरोधी नियमों के अनुसार रिकॉर्ड में "उपलब्ध तथ्यों" के आधार पर अपने जाँच परिणाम दर्ज कर सकते हैं ।

15. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा प्रस्तुत मामले में अपने हितों के बारे में सूचित करने (हित के स्वरूप सहित) और प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत करने एवं पाटनरोधी उपायों को जारी रखने अथवा न रखने की आवश्यकता के बारे में घरेलू उद्योग के आवेदन पर अपनी टिप्पणियां इस जांच की शुरुआत की तारीख से 40 दिनों के भीतर प्रस्तुत करने की सलाह दी जाती है।

गोपनीय आधार पर सूचना उपलब्ध कराना

16. यदि प्रश्नावली के उत्तर/निवेदन के किसी भाग के लिए गोपनीयता का दावा किया जाता है तो उसे दो अलग-अलग सेटों में प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित होगा (क) गोपनीय रूप में चिह्नित, शीर्षक, सूची, पृष्ठों की संख्या इत्यादि सहित तथा (ख) दूसरा सेट अगोपनीय के रूप में चिह्नित (शीर्षक, सूची, पृष्ठों की संख्या इत्यादि सहित)। प्रस्तुत की गई प्रत्येक सूचना के प्रत्येक पृष्ठ के सबसे उपर स्पष्ट रूप से "गोपनीय" अथवा "अगोपनीय" चिह्नित होना आवश्यक है।

17. किसी चिह्न के बिना प्रस्तुत की गई सूचना को अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी के पास अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी अगोपनीय सूचना का अवलोकन करने की अनुमति देने का अधिकार होगा। गोपनीय तथा अगोपनीय रूपांतर की दो-दो (2) प्रतियां प्रस्तुत की जानी चाहिए।

18. जिस सूचना के लिए गोपनीयता का दावा किया गया हो, उस सूचना के आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत सूचना के साथ इस बात का ठोस कारण बताते हुए एक विवरण प्रस्तुत करना अपेक्षित है कि ऐसी सूचना को क्यों प्रकट नहीं किया जा सकता तथा/अथवा ऐसी सूचना का सारांश करना क्यों संभव नहीं है।

19. अगोपनीय रूपांतर, गोपनीय रूपांतर की प्रतिकृति होना चाहिए जिसमें सूचना की गोपनीयता के दावे के आधार पर गोपनीय सूचना को सूचीबद्ध किया जाए/अथवा वह स्थान रिक्त रखा जाए। अगोपनीय सारांश पर्याप्त रूप से विस्तृत होना चाहिए जिससे गोपनीय आधार पर उपलब्ध कराई गई सूचना का अर्थ समुचित रूप से स्पष्ट हो सके। तथापि आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाला पक्षकार यह निवेदन कर सकता है कि प्रस्तुत की गई सूचना का सारांश करना संभव नहीं है, ऐसी स्थिति में प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए सारांश संभव न होने का कारण बताते हुए एक विवरण प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा।

20. प्रस्तुत की गई सूचना की प्रकृति की जांच करने के पश्चात प्राधिकारी द्वारा गोपनीयता हेतु अनुरोध को स्वीकार अथवा अस्वीकार किया जा सकता है। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध आवश्यक नहीं है अथवा सूचना प्रस्तुत करने वाला सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है अथवा सामान्य सारांश रूप से उसका प्रकटन करने के लिए प्राधिकृत नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना को नजरअंदाज कर सकते हैं।

21. प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई किसी सूचना को उसके साथ उसके एक सारगर्भित अगोपनीय रूपांतर अथवा गोपनीयता का दावा करते हुए ठोस कारण दर्शाते हुए विवरण के बिना, अस्वीकार किया जा सकता है। प्राधिकारी प्रस्तुत सूचना की गोपनीयता के बारे में संतुष्ट होने तथा गोपनीयता की आवश्यकता को स्वीकार करने के पश्चात, ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना उस सूचना को किसी पार्टी के समक्ष प्रकट नहीं करेंगे।

सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

22. नियम 6(7) के अनुसार कोई भी हितबद्ध पक्षकार अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के अगोपनीय सारांश वाली उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है।

असहयोग

23. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है या उचित समय के भीतर उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

विजयलक्ष्मी जोशी, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 13th March, 2012

Subject : Sunset Review of anti-dumping duty imposed concerning imports of 'Peroxisulphates' (also known as 'Persulphates') originating in or exported from China PR and Japan.

No. 15/9/2011-DGAD.—Whereas having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Antidumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred to as the AD Rules), the definitive anti-dumping duty was originally recommended vide notification No. 14/1/2006-DGAD dated 20th July, 2007 on imports of 'Peroxisulphates' also known as 'Persulphates' (hereinafter also referred to as the subject goods) originating in or exported from China PR and Japan (hereinafter referred to as the subject countries) and whereas the Central Government issued Notification No. 96/2007 - Customs, dated 29th August, 2007 imposing the said anti dumping duties.

2. Whereas, M/s Gujarat Persalts Pvt. Limited, M/s Calibre Chemicals Pvt. Limited, M/s VR Persulphates and M/s Yoyo Chemicals, have jointly filed a duly substantiated application in accordance with the Act and the AD Rules before the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) alleging dumping of the subject goods originating in or exported from the subject countries, and have requested for review, continuation and enhancement of the anti-dumping duties.

Domestic industry

3. The application has been jointly filed by M/s Gujarat Persalts Pvt. Limited, M/s Calibre Chemicals Pvt. Limited, M/s VR Persulphates and M/s Yoyo Chemicals. The Applicants have claimed that they represent the domestic industry as they are the only domestic producers of the subject goods. As per information available on record, the Applicants account for the total Indian production of the subject goods and hence constitute the domestic industry in terms of the AD Rules.

79748/12-2

Product under consideration and Like Article

4. The product involved in the original investigation was 'Peroxisulphates' (also known as 'Persulphates'). This being a Sunset review investigation; therefore, the investigation covers the same product, as was covered in the original investigation. Persulphates are a group of closely related compounds. These are produced as Alkali Metal salts which include Ammonium Persulphates (APS), Potassium Persulphates (PPS) and Sodium Persulphates (SPS).

5. The Chemical Formula of these 'Persulphates' are, respectively, $(\text{NH}_4)_2\text{S}_2\text{O}_8$, $\text{K}_2\text{S}_2\text{O}_8$, $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_8$. The three types of 'Persulphates' have the same end-uses as an initiator and oxidizing agent in the textile and chemical industries and one can be substituted for another. All three salts are one and same product. 'Persulphates' are used as an initiator and oxidizing agent in the textile and chemical industries.

6. 'Persulphates' are classified in Chapter 28 of the Customs Tariff Act, 1975 under subheading 2833 40 and under subheading 28334000.

7. The domestic industry also produces 'Persulphates' having similar characteristics and specifications. No argument has been extended, by any interested party in the previous investigation, on the issue of product under consideration or like article. The present investigation is a Sunset review of the anti dumping duty earlier imposed. Therefore, the Authority considers that the product being manufactured by the domestic industry is 'like article' to the product under consideration as per the AD Rules.

Initiation:

8. In view of the duly substantiated application filed on behalf of the domestic industry and in accordance with Section 9A(5) of the Act, read with Rule 23 of the AD Rules; the Authority hereby initiates a Sunset review investigation, to review the need for continued imposition of the anti-dumping duties in force in respect of the subject goods from the subject countries and to examine whether the expiry of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.

Countries involved:

9. The countries involved in this investigation are China PR and Japan.

Period of Investigation:

10. The Period of Investigation (POI) for the purpose of the present review is 1st January 2011 to 31st December 2011 (12 months). However, injury analysis shall cover the years 2008-09, 2009-10, 2010-11 & POI. The data beyond POI may also be examined to determine the likelihood of dumping and injury.

Procedure:

11. The review covers all aspects of Notification No. 14/1/2006-DGAD, dated 20th July, 2007 (final findings of the original investigation).

12. The provisions of Rules 6,7,8,9,10,11,16,17,18,19 and 20 of the Rules supra shall be mutatis mutandis applicable in this review.

Submission of Information:

13. The known exporters in the subject countries, the government of the subject countries through its embassy in India, the importers and users in India known to be concerned with the product are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Authority at the following address:

**Designated Authority
Government of India
Ministry of Commerce and Industry
Directorate General of Anti-Dumping and Allied Duties
Department of Commerce
Room No.240, Udyog Bhawan,
New Delhi-110107.**

Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below.

Time Limit:

14. Any information relating to the present review and any request for hearing should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 days) from the date of publication of this Notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the AD Rules.

15. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire's responses and offer their comments to the domestic industry's application regarding the need to continue or otherwise the AD measures within 40 days from the date of initiation of this investigation.

Submission of information on confidential basis.

16. In case confidentiality is claimed on any part of the questionnaire's response/submissions, the same must be submitted in two separate sets (a) marked as confidential (with title, index, number of pages, etc.) and (b) other set marked as non-confidential (with title, index, number of pages, etc.). All the information supplied must be clearly marked as either "confidential" or "non-confidential" at the top of each page.

17. Information supplied without any mark shall be treated as non-confidential and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect any such non-confidential information. Two (2) copies each of the confidential version and the non-confidential version must be submitted.

18. For information claimed as confidential; the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed and/or why summarization of such information is not possible.

19. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out / summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible of summary; a statement of reasons why summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.

20. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

21. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim may not be taken on record by the Authority. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided; shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

Inspection of public file:

22. In terms of rule 6(7) any interested party may inspect the public file containing non-confidential versions of the evidence submitted by other interested parties.

Non-cooperation

23. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Governments as deemed fit.

VIJAYLAXMI JOSHI, Designated Authority